SHRI JAGANNATH PAHADIA : It has been said that a statement will be made tomorrow. Therefore, the hon. member can wait till then.

श्री बलराज मधोक : एल० आई० सी० के पिछले पांच सात साल के अनुभव से एक बात स्पष्ट हो गई है कि सारे लाइफ़ इन्शोरेंस पर सरकार का कब्ज़ा होने के कारण, उस पर सरकार की मानोपली होने के कारण, उस की एफ़िशेंसी कम हुई है और उस का रीयल विज़िनेस भी बढ़ा नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : बढ़ा है ।

श्री बलराज मधोक : कैसे बढ़ गया है, लेकिन रीयल विज़िनैस नहीं बढ़ा है । इस लिए सरकार भी सोचती है कि उस को कुछ हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाये, ताकि उन में काम्पीटीशन हो और काम बढ़े । क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार जेनेरल इन्शोरेंस की बात करती है, तो वह इस बात का ध्यान रखेगी कि उस पर किसी प्रकार का मानोप्लिस्टिक कंट्रोल न हो, चाहे वह प्राईवेट सैक्टर का हो और चाहे स्टेट सैक्टर का हो, और उस में काम्पीटीशन का एलिमैंट रहे, क्योंकि अगर उस में काम्पीटीशन होगा, तो कम्ज्यूमर और इनशोरर को लाभ होगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यह दृष्टिकोण सामने है ही ।

श्री बीजू पटनायक के समवाय

+

*811—क. **श्री निहाल सिंह :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री बीजू पटनायक की कौन कौन सी फर्में विदेशों में हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने श्री बीजू पटनायक को विदेशों में जाने के लिए पारपत्र दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री बीजू पटनायक को विदेशों में फर्में स्थापित करने की अब तक कोई अनुमति नहीं दी गयी है ।

(ख) और (ग). प्रार्थनापत्र के मिलने पर श्री पटनायक का पारपत्र 19 मई, 1967 को फिर से नया कर दिया गया था, क्योंकि उनका मामला पारपत्र अधिनियम 1967 के निषेधात्मक खण्डों के अन्तर्गत नहीं आता ।

उड़ीसा की सरकार ने श्री पटनायक के पारपत्र को फिर से नया न करने की प्रार्थना की थी क्योंकि वह सरकार राज्य के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध कुछ कथित आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना चाहती थी । यह प्रार्थना मंजूर नहीं की जा सकी क्योंकि जो कारण बताये गये थे उनसे पारपत्र को अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता था ।

श्री निहाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि बीजू पटनायक की कम्पनियों पर जो सरकारी रकम बाकी है, क्या उसे बचाने के लिए ही उन्हें पारपत्र दिया गया था ।

श्री मोरारजी देसाई : यह बात बिल्कुल ग़लत है ।

LOANS TO STATES

*812. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the steps which Planning Commission have taken and propose to take to see that the amount advanced to the State Governments and Departments of the Central Government is spent in time, efficiently and properly for the purposes earmarked and measures to be taken in cases of violation of conditions or deviation from main purposes; and

(b) the loans outstanding against the States, state-wise, and the prospects of their repayment?